



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939

No. 25]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

**जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

**ओआई-47/2017**

**विषय : चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, हांगकांग और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल फिल्म के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच**

**फा. सं. 6/44/2017-डीजीएडी.—**मै. गरवारे पालिएस्टर लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, हांगकांग और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से सन और/या डस्ट कंट्रोल फिल्म (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

3. यह आवेदन मै. गरवारे पालिएस्टर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक है आवेदक का पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वह संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

4. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं और बाजार में नये प्रवेशक हैं। इस प्रकार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है; वास्तव में घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अधीन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

5. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद में (पीयूसी) सन और/या डस्ट क्रट्रोल फिल्म शामिल है, यह एक प्रकार की विशेष पालीथिलीन/पालिएस्टर फिल्म है। सन और/या डस्ट क्रट्रोल फिल्म एक प्रकार की सेल्फ एधेसिव प्लेट, शीट, फिल्म, फोइल, टेप, स्ट्रिप और प्लास्टिक के अन्य फ्लेट शेप होते हैं चाहे रोल्स में हों अथवा नहीं। विचाराधीन उत्पाद को व्यापार और बाजार शब्दावली में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे सन फिल्म, सन और/या डस्ट क्रट्रोल फिल्म, विंडो फिल्म, सोलर फिल्म, सोलर कंट्रोल फिल्म, सोलर विंडो फिल्म आदि। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में प्लेन या मेटलाइज्ड पालीथिलीन/पालिएस्टर फिल्म शामिल नहीं है।

### **समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

7. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" माना है।

**शामिल देश**

8. वर्तमान जाँच चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, हांगकांग और कोरिया गणराज्य (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

**सामान्य मूल्य****चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, हांगकांग और कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

9. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि चीन जन. गण. में उद्योग में काफी विकृतियां प्रचलित हैं। अतः, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान भारत में उत्पादन के आधार पर घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत; घरेलू उद्योग की सुविधाओं की लागत और परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

**निर्यात कीमत**

10. आवेदक ने डीजीसीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़ों पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित की है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निर्यातक देश के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े के व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच को उचित ठहराते हैं।

**क्षति और कारणात्मक संबंध**

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुई क्षति के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है जिसका उदाहरण विभिन्न मापदंडों जैसे समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी, भारी कीमत कटौती, निरंतर वित्तीय घाटों, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूची आदि में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह

नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मापदंडों जैसे लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में कमी आई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेशों पर ऋणात्मक आय झेलना पड़ रहा है।

14. और यतः, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

### **पाटनरोधी जाँच की शुरुआत**

15. पूर्वोक्त पैराग्राफों के मद्देनज़र, निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **जाँच अवधि (पीओआई)**

16. आवेदक ने अप्रैल 2016 से जून 2017 (15 महीनों) के लिए सूचना प्रदान की है। तथापि क्षति जाँच अवधि पर 2013-14, 2014-15, 2015-16, और प्रस्तावित जाँच अवधि के रूप में विचार किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित जाँच अवधि को उचित पाया है।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**  
**वाणिज्य विभाग,**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने

उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता या अन्यथा के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2018

(Case No. OI-47/2017)

**Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of Sun/Dust control film originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Hong Kong and Korea RP.**

**No. 6/44/2017-DGAD.**—M/s. Garware Polyester Limited (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Sun and/or dust control film (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration) from China PR, Chinese Taipei, Hong Kong and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Domestic Industry & Standing**

3. The petition has been filed by M/s Garware Polyester Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India and the applicant accounts for 100% production of the product under consideration in the Indian Production during the POI. The applicant has certified that they are not related to a producer/exporter of the product under consideration in subject countries or an importer in India.

4. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject goods in India and a new entrant in the market. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production; in fact 100% share of domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti- Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the anti- dumping Rules.

**Product under consideration**

5. The product under consideration in the present case is Sun and/or dust control film is a kind of specialty polyethylene/polyester film. Sun and/or dust control film in the form of Self Adhesive plate, sheet, film, foil, tape, strip and other flat shapes of plastics whether or not in rolls. The product under consideration is known by different names in the trade and market parlance, such as Sun films, Sun and/or dust control film, Window Film, Solar films, Solar Control Films, Solar Window Films etc. The scope of the product under consideration excludes plain or metallized polyethylene/polyester films.

**Like Article**

6. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

7. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject country.

**Countries involved**

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR, Chinese Taipei, Hong Kong and Korea RP (referred to as the subject countries).

**Normal Value****Normal Value for China PR, Taipei, Hong Kong and Korea RP**

9. The petitioners have submitted that they have not been able to collect domestic selling prices of the subject goods in the subject countries. The petitioners also claim that there is significant distortions prevailing in the Industry in China PR. Therefore, the Normal Value in the subject countries has been estimated on the basis of cost of production in India; taking into account cost of raw material of domestic industry, cost of utilities and conversion cost of domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

**Export Price**

10. The applicant has determined the export price of the subject goods from the subject countries by considering transaction wise import data collected from the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses in the exporting country to arrive at ex-factory export price.

**Dumping Margin**

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. There is sufficient evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

**Injury and Causal Link**

12. The applicant has furnished evidence regarding injury due to alleged dumping due to increased imports in absolute terms and relative to production and consumption in India, price depression, price underselling and adverse impact on profitability, return on capital employed, and cash flow of the domestic industry.

13. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports exemplified by various parameters such as significant increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, significant price undercutting, continued financial losses, return on investments, cash flow, inventories, etc. The demand for the product under consideration has increased throughout the injury period and subject imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments.

14. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation.

**Initiation of anti-dumping investigations**

15. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Period of Investigation (POI)**

16. The applicant has provided information for the period April 2016 to June 2017 (15 months). The injury investigation period has however, been considered as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16 and proposed POI. The Authority finds the period of investigation, proposed by the applicant, is appropriate for the purposes of the present investigation.

**Submission of information**

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.**

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of Information on Non-Confidential basis**

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.